प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 36 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 11 – 18 सितम्बर 2017 मूल्य पांच रूपए

वीरभद्र हाईकमान से टकराव क्यों ले रहे है

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नही लड़ेंगे? लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। इन चुनावों में पार्टी को लीड करेंगे या नही करेंगे? इन सवालों पर अब तक संशय बना हुआ है क्योंकि इस संद्धर्भ में उनके ब्यान बराबर बदलते आ रहे हैं। इस बारे में अगर कुछ स्पष्ट है तो सिर्फ इतना कि इस समय उनकी राजनीतिक प्राथमिकता सुक्खु को अध्यक्ष पद से हटवाना बन गया है। ऐसे में यह सवाल उठता जा रहा है कि यदि सुक्खु अध्यक्ष पद से नही हटते हैं तो वीरभद्र का अगला कदम क्या होगा? वीरभद्र को हाईकमान का क्या रूख रहता है? इस पर सुक्खु और वीरभद्र से असहमति रखने वाले दूसरे नेताओं का स्टैण्ड क्या होता है? यह सवाल इस प्रदेश कांग्रेस के लिये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है जबकि भाजपा ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस के खिलाफ पूरा हमला बोल रखा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह 22 को कांगड़ा में आयोजित होने जा रही हुंकार रैली में इस हमले को और भी धार देने वाले हैं। भाजपा के हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सामने आने का साहस नही जुटा पा रहा है। ऊपर से यह भ्रम भी फैला हुआ है कि कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर कभी भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि कुछ नेताओं का आचरण ही इसके स्पष्ट सकेंत दे रहा है।

इस परिदृष्य में यह आंकलन महत्वपूर्ण हो जाता है कि वीरभद्र ऐसा स्टैण्ड ले क्यों रहे है? वीरभद्र हर चुनाव में पार्टी पर अपना एक छत्र अधिकार चाहते हैं और जब ऐसा होने में कोई बाधा आती है तब वह बगावत के किसी भी हद तक चले जाते है। 1983, 1993 और 2012 में घटे घटनाक्रमों की जानकारी रखने वाले यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हाईकमान को उनकी शर्ते माननी ही पड़ी है लेकिन क्या इस बार भी ऐसा हो पायेगा? क्योंकि इस समय के वीरभद्र के अपने खिलाफ जो मामले खड़े हैं यदि उनके दस्तावेजी प्रमाण चुनाव अभियान के दौरान सार्वजनिक चर्चा में आ खड़े होते है तो वीरभद्र और पूरी पार्टी के लिये संकट खड़ा हो जायेगा। 2014 के लोकसभा चुनावों में जब इन मामलों की चर्चा उठी थी तो कांग्रेस को 68 में से 65 हल्को में हार का मुख देखना पड़ा था जनता भ्रष्टाचार के आरोपों पर जितने विरोध में आ जाती है उतना समर्थन वह विकास कार्यो पर नही देती है यह एक राजनीतिक सच बन चुका है और इसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है यह भी स्पष्ट हो चुका है। इसके बावजूद वीरभद्र पूरी पार्टी को ऑखे दिखा रहे हैं। जबकि चुनाव सरकार की परफारमैन्स पर लड़ा जाता है अकेले पार्टी के प्रचार अभियान के दम पर नही और इस समय सरकार की छवि माफिया राज बनती जा रही है। विकास के नाम भी जो काम ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र और शिमला के शिमला ग्रामीण में हुए उनके मुकाबले में दूसरे क्षेत्रों में तो 10% भी नहीं है। कांग्रेस के अपने ही विधायक इसकी शिकायतें करते रहे हैं। यही कारण है कि यह लोग आज खुलकर वीरभद्र के साथ खड़े नही हो पा रहे हैं। क्योकि इन विधायकों को नजरअन्दाज करके इनके क्षेत्रों से जिन लोगों को विभिन्न निगमो/वार्डो में ताजापोशीयां दी गयी थी वह सब आज समानान्तर सत्ता केन्द्र बनकर टिकट के दावेदार बने हुए है। इनमें से अधिकांश को ताजपोशीयां विक्रमादित्य की सिफारिश पर मिली है और वहीं विक्रमादित्य की अपनी राजनीतिक ताकत भी बने रहे हैं। इन्ही की ताकत पर विक्रमादित्य समय – समय पर चुनाव टिकटों के वितरण के लिये मानदण्ड तय करने को लेकर ब्यान देते रहे है।

ऐसे में माना जा रहा है कि वीरभद्र सिंह पर विक्रमादित्य के अधिक से अधिक समर्थकों को टिकट दिलवाने का दवाब है जबकि जिन क्षेत्रों से पार्टी के पास मौजूदा विधायक है वहां पर इन लोगों को टिकट देना आसान नही। सुक्खु बतौर कांग्रेस अध्यक्ष वर्तमान विधायकों के लिये एक मात्र सहारा रह गये हैं क्योंकि यह ब्यान आते रहे हैं कि कई वर्तमान विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। विक्रमादित्य के समर्थकों को टिकट तभी सुनिश्चित हो सकते हैं यदि टिकट बंटवारे पर केवल वीरभद्र सिंह का ही अधिकार रहे। अन्यथा वीरभद्र का सुक्खु से और क्या विरोध हो सकता है। शिंदे ने भी संभवत: इसी व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर यह कहा था कि चुनाव वीरभद्र की ही लीडरशीप मे लड़े जायेंगे लेकिन सुक्खु को भी नही हटाया जायेगा लेकिन वीरभद्र इस आश्वासन से भी सन्तुष्ट नही हुए तो स्पष्ट है कि वह इस समय पार्टी की सिफारिश पर नही वरन् अपनी ईच्छा से टिकट वितरण चाहते हैं और यह तभी संभव है जब सुक्खु अध्यक्ष न रहे। माना जा रहा है कि वीरभद्र सिंह अर्की के कुनिहार में 25 तारीख को भाजपा की हुंकार रैली के जवाब में एक उससे भी बड़ी रैली आयोजित करने जा रहे है। इस रैली में वीरभद्र अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगें यदि यह रैली वीरभद्र की ईच्छा के अनुसार एक सफल रैली हो जाती है तो संभव है कि एक बार फिर हाईकमान वीरभद्र की शर्तो को मान ले। लेकिन इस रैली का सफल होना इस पर निर्भर करता है कि क्या अमितशाह की 22 की रैली में कांग्रेस का कोई नेता भाजपा में शामिल होता है या नही। अभी हर्षमहाजन ने जिस तरह से जीएस बाली और वीरभद्र में फिर से बैठकें करवाई हैं उसे इसी प्रयास के रूप मे देखा जा रहा है।

अब रवि शंकर प्रसाद ने बोला वीरभद्र पर बड़ा हमला

शिमला/शैल। अपनी करतूतों को छिपाते हुए मोदी सरकार के काबीना मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर हमला करते हुए कहा कि ये पहली बार है कि देश की कोई सरकार बेल पर है। उन्होंने कहा कि अगर वो कानूनी तौर पर कहे तो एजेंट जेल में व प्रिंसिपल बेल पर।

वो भाजपा की ओर से चलाए हिमाचल मागे हिसाब अभियान की श्रृंखला की तीसरी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राजधानी शिमला में मीडिया से रूबरू हुए।

मोदी सरकार के कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ये खुलासा नहीं किया कि एजेंट ही जेल में क्यों है और प्रिंसिपल बेल पर क्यों है। वो जेल में क्यों नहीं हैं। क्या एजेंट का अपराध बड़ा है या प्रिंसिपल का। उन्होंने ये भी खुलासा नहीं किया कि इस खेल के पीछे मोदी सरकार का हाथ है या नहीं। दुनिया में अब तक ऐसी कोई भी सरकार सता में नहीं रही है जिसने एजेंट को तो जेल में डाला हो और असली मुलजिम को बाहर रखा है। मुख्यमंत्री के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान पिछले सवा साल से जेल में हैं। इन्हें इडी ने गिरफ्तार किया है। रवि शंकर प्रसाद प्रेस कांफ्रेंस में इन्हीं एजेंट की बात कर रहे थे।

याद रहे सीबीआई की ओर दर्ज एफआईआर में वीरभद्र सिंह को हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ था लेकिन ईडी की ओर से मनी लांड्रिंग के केस में कभी भी किसी भी अदालत ने उनके व बाकी आरोपियों के अरेस्ट पर कभी रोक नहीं लगाई थी। ईडी ने केवल वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को ही अरेस्ट किया बाकी को छुआ तक नहीं। इस मसले पर पूरी मोदी सरकार सवालों में हैं। मोदी सरकार से भी हिसाब लेना बनता है।

देश के कानून व आईटी मंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने कानून के सारे औजारों का इस्तेमाल किया। एफआईआर रदद करने से लेकर आरोपों से मुक्त करने तक की अर्जी अदालत

में डाली लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया और ट्रायल चलेगा ये फैसला दिया।

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इन सब वजह से प्रदेश में गवर्नेंस की कैजुअल्टी हो गई। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार व वितीय बेइमानी के गंभीर आरोप हैं।

मोदी सरकार में मंत्री व हिमाचल से भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार जगत प्रकाश नड्डा के गहरे मित्र रवि शंकर प्रसाद ने भाजपा की ओर से हिमाचल से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसका सीधा जवाब नहीं दिया। वो बोले, ये फैसला पार्लियामेंटरी बोर्ड करेगा। इस एक सवाल पर पूरी भाजपा मौन है।

विकास की जो इबारत बार – बार जेपी नड्डा गिनवाते हैं उन्होंने भी वही इबारत गिनवाई व कहा कि हिमाचल में 20623 किलोमीटर नेशनल हाइवे हैं। इसमें से 740 किलोमीटर एनएचएआइ के तहत हैं। जिनकी फंडिंग मोदी सरकार कर रही हैं। 740 किलोमीटर में से 243 किलोमीटर पर काम प्रोग्रेस में हैं। 41 किलोमीटर के ठेके दे दिए गए हैं। 250 किमी का डीपीआर बन गया हैं। वीरभद्र सरकार के तहत 1900 किलोमीटर रोड़ हैं। किसी का भी डीपीआर नहीं बनी हैं। डीपीआर के 298 करोड़ रुपए भी अदा कर दिए हैं। लेकिन डीपीआर नहीं बनी हैं।

उन्होंने कहा कि 13वें वितीय आयोग ने पांच सालों के प्रदेश के लिए 21691 रुपया दिया था लेकिल 14वें वितायोग के तहत मोदी सरकार ने हिमाचल के लिए पांच सालों के लिए 75 हजार 281 करोड़ 28 लाख रुपया दिया हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने प्रदेश के लिए एक लाख 25 हजार करोड रुपया दे दिया हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार पैसा भेज रही हैं लेकिन सदुपयोग नहीं हो रहा हैं। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से राजधानी शिमला तक का रोड़ बदहाल। जब इस महत्वपूर्ण रोड़ की ये स्थिति तो प्रदेश में क्या स्थिति होगी।

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने गरीबों की कल्याणकारी योजना के 58 हजार करोड रुपए बचाए हैं। ये डिजिटल तकनीक की वजह से हुआ। मोदी सरकार गरीबों के खाते में हजारों भेजती हैं तो उनके खातों में हजारों ही पहुंचते हैं। बचौलिए खत्म कर दिए हैं। डिजिटाइलेजेशन की वजह से अढाई करोड़ जाली राशन बाहर हो गए और सवा करोड़ गैस कनैक्शन बाहर कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के दरबार से लॉबीस्टि बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला व कहा कि व विदेशों में थोड़ा ज्ञानवान हो जाते हैं।

तीन तलाक के मसले को छूते हुए उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी का स्टैंड इस मामले में साफ था बाकी कोई भी पार्टी खुल के नहीं आई। ये धर्म, इबादत या यारीअत का मामला नहीं हैं।

शेष पृष्ठ 8 पर.....

शैल समाचार के नियमित पाठक बनने हेतू विज्ञापन देने के लिये इन नम्बरों पर संपर्क करें

कार्यालय दूरभाष - 0177 - 2805015, मो. 8988587014, मो. 9418069978, मो. 9418020312
ई मेल – shailsamachar@gmail.com, वेबसाईट – www.shailsamachar.co.in

पाठकों की प्रतिक्रियाओं को भी विशेष स्थान दिया जायेगा
– संपादक

राज्य बाल कल्याण परिषद् की शासी निकाय की बैठक में उपायुक्तों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य बाल कल्याण परिषद् द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न आश्रमों व गृहों के नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए गठित स्थानीय प्रबंधन समितियों की हर तीन माह में बैठक आयोजित होनी चाहिए ताकि यहां रह रहे बच्चों के कल्याण के लिए वे अपने

महत्वपूर्ण सुझाव दे सकें।

राज्यपाल राजभवन में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद् की शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी बैठक में उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि बच्चों की मनोदशा को बेहतर समझने के लिए स्थानीय समिति में एक मनोचिकित्सक भी होना चाहिए तथा परिषद् द्वारा संचालित प्रत्येक आश्रमों में परामर्श की विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये समितियां अपने सुझाव दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर का रखरखाव भी सुनिश्चित बनाएं, जिसपर परिषद् की बैठक में चर्चा की जा सके ताकि आश्रमों में रह रहे बच्चों के कल्याण के लिए ठोस निर्णय लिए जा सकें।

आचार्य देवव्रत ने देश के कुछ संस्थानों में अप्रत्याशित घटनाओं के मद्देनजर प्रत्येक आश्रम में सी.सी.टी.वी कैमरे स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि उनका सुचारू संचालन व निगरानी सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए। उन्होंने आश्रमों में रहे रहे बच्चों के प्रति गंभीरता एवं मानवीयता बनाए रखने की अपील की तथा कहा कि ऐसे केंद्रों की देखरेख के लिए पात्र व प्रशिक्षित व्यक्ति तैनात किए जाने चाहिए, जो विवेकशीलता के साथ अपना कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र में रह रहे बच्चों के साथ नियमित विचार-विमर्श से उनमें विश्वास और मानवतावादी विचारों को पैदा करने में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल ने आश्रमों व गृहों के बेहतर रखरखाव के लिए प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह अक्सर इन केंद्रों में जाते हैं और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था समाज में विश्वास पैदा करती हैं। समाज में बढ़ती नशे की प्रवृति पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अधिकांश अपराध एवं दुर्घटनाएं नशे के कारण की होती हैं, जिनपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने राज्य बाल कल्याण परिषद् की शासी निकाय की वार्षिक बैठक में उपायुक्तों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार बेसहारा, विशेष सक्षमता वाले बच्चों तथा निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और इनमें से कुछ योजनाएं हि.प्र. बाल कल्याण परिषद के माध्यम से संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 308 बच्चों वाले बाल एवं बालिका आश्रम के संचालन के परिषद को अनुदान प्रदान कर रही है।

उन्होंने शिमला के समीप ढली में विशेष स्कूल के दिव्यांग बच्चों के लिए 805.48 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने परिषद को निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के गरली में बालिका आश्रम भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इसका शीघ्र लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद द्वारा कामकाजी महिलाओं के 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राज्य में 42 शिशु सदन चलाए जा रहे और राज्य सरकार इनके उपयुक्त संचालन के लिए परिषद को सहायता अनुदान भी प्रदान कर रही है। उन्होंने सरकार द्वारा बेसहारा तथा निराश्रित बच्चों के कल्याण तथा उत्थान के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रयास करने के निर्देश दिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा.(कर्नल) धनीराम शाण्डिल ने कहा कि राज्य में बेसहारा, निराश्रित तथा दिव्यांग बच्चों को भोजन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 29 बाल-बालिका गृह, एक सप्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह तथा तीन खुले आश्रम संचालित किए जा रहे हैं । इनमें से 10 गृह राज्य सरकार द्वारा तथा 19 बाल आश्रम व तीन खुले आश्रम गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि हि.प्र. बाल कल्याण परिषद द्वारा विशेष बच्चों के लिए 9 बाल-बालिका आश्रम एवं स्कूल तथा शिशु गृह संचालित किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन गृहों में 1208 आश्रय ले रहे है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Sealed item rate tender on the form NO 6 &8 are invited by the Executive Engineer Nalagarh Division HP PWD Nalagarh on behalf of the Governor Of Himachal Pradesh From the approved and eligible contractors enlisted in HP PWD, in the appropriate class for the work mentioned below in the presence of contractor or their authorized representative.

Time schedule of tender:-

(1)The last Date & time of receipt of Application for tender Form — 11-10-2017up to 11.00 A.M .
(2) The last date of issue of tender form: — 11- -10 -2017 up to 4.P/.M
(4) The date of opening of tender: — 12- 10-2017 up to 11A.M

Earnest money in the shape of National Saving certificate/ Time Deposit accounts/ Saving accounts in any of the Post Office/ Bank in H.P duly pledged in f avour of the Xen HP PWD Nalagarh must be accompanied with the tender documents. The conditional tender and the tender received Without earnest money will be summarily rejected. The Executive Engineer reserves right to accept or reject any or all tenders ,the tenders shall be kept open for 120 days.

The contractor should be registered as dealer Under HP sale Tax Act 1968 and also produce sale tax clearance certificate from the Excise and Taxation Department.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnst Money	Time	Cost of form
1.	Construction of Link road to village upperla Mahadev to Nichla Mahadev K.m 0/0 to 0/600 (SH C/O abutment of 10.00 mtr Span rcC Slab culvert)	9,90,887/-	20,000/-	Two months	350/-

Term and conditions :-

1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2. Earnest money should be accompanied with application application without earnest money will not be entertained.
3. The photocopy of Pan Number should be attached with the application other wise tender form will not be issued.
4. The photocopy of Sale Tax number should be attached with the application other wise tender form will not be issued.
5. The photocopy of Valid enlistment/ registration of contractor or E.P.F/ g.S.T Number should be attached with the application other wise tender form will not be issued .
6. The contractor will have to submit affidavit alongwith application for issue of tender that he has not more than two work in hand.
7. The Contractor will have to submit the proof of ownership of Machinery .

Adv. No.-2692/17-18 — HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

अपनी मातृ भाषा पर गर्व करें राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हमें अपनी मातृ भाषा और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हिन्दी एकमात्र ऐसी भाषा है, जो देश को एकसूत्र में बांध सकती है।

राज्यपाल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित राजभाषा हिन्दी सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि दुनिया के लगभग सभी विकसित राष्ट्रों ने अपनी भाषा के दम पर विकास की ऊंचाइयों को हासिल किया है और विकास के हर क्षेत्र में मातृ भाषा को अपनाकर आगे बढ़े हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो राष्ट्र आज महाशक्ति के रूप में उभरे हैं उसके पीछे उनकी भाषा की ताकत है। जबकि देश में आजादी के बाद भाषा के नाम पर 'पाखण्ड' से ही हिन्दी को काफी नुकसान हुआ।

उन्होंने चिंता जताई कि देश के अधिकांश उच्च संस्थानों व कार्यालयों में भाषा के नाम पर हम आम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं और विदेशी भाषा की प्राथमिकता से आम आदमी अपनी बात से वंचित हो रहा है। आजादी के बाद भी अंग्रेजों की मानसिक गुलामी इस देश से नहीं गई, जबकि जापान व इजराइल जैसे छोटे राष्ट्र अपनी मातृ भाषा को अपनाकर दुनिया में अपनी तकनीक का लोहा मनवा रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि हिन्दी समारोह का आयोजन कर केवल औपचारिकताएं नहीं निभाई जानी चाहिए, इसे व्यवहारिक रूप दिया जाना चाहिए। दुनिया के 123 से अधिक देशों में हिन्दी बोली जाती है। उन्होंने कहा कि देश से उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का विदेशों के लिए पलायन केवल हिन्दी भाषा में शिक्षा को देकर ही रोका जा सकता है।

उन्होंने विभाग द्वारा हिन्दी को प्रोत्साहन देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा प्रदेश भर से आए विद्यार्थियों तथा सरकारी कर्मियों को पुरस्कार के लिए चयनित होने पर बधाई दी। उन्होंने आग्रह किया कि मातृ भाषा को पूर्ण रूप से अपनाकर दूसरों को भी प्रेरित करें तभी देश में बदलाव लाया जा सकता है।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने विभागीय वार्षिक राजभाषा पत्रिका, संस्कृति तथा बिलासपुर की संस्कृति पुस्तकों का विमोचन भी किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं बोर्डों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने विभिन्न स्पर्धाओं के विजेता विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया।

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी पखवाड़ा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश कोरला ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

2018 में होगी 42 सार्वजनिक व 11 वैकल्पिक छुट्टियां

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 के लिए कुल 42 सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की है, जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए तीन राजपत्रित अवकाश, राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों/ बोर्डों/ निगमों/शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अलग से 16 राजपत्रित अवकाश भी शामिल हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी कर्मचारी वर्ष के दौरान कोई दो वैकल्पिक अवकाश की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2018 के दौरान जिलों में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण मेलों एवं त्यौहारों के लिए संबंधित उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र में दो स्थानीय अवकाश घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

आम जनमानस स्वच्छता अभियान में बढ़-चढ़ कर भाग ले:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव वी. सी. फारका ने राज्य में 15 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 2017 तक आयोजित किए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़े व इसके उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 'स्वच्छता ही सेवा है' उद्देश्य को लेकर इस पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश भर में 15 सितम्बर को कार्यक्रम का आरम्भ होगा। उन्होंने कहा कि 17 सितम्बर का दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रमदान होगा, 24 सितम्बर का दिन समग्र स्वच्छता के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें शहर के स्थानीय लोग, युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे, खिलाड़ी, चुने हुए जन प्रतिनिधि, धार्मिक संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह व अन्य सभी संस्थान श्रमदान करेंगे और स्वच्छता के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग करेंगे।

फारका ने कहा कि 25 सितम्बर का दिन सर्वत्र स्वच्छता के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन अस्पतालों, पार्कों, बस अड्डों, कुओं, शौचालयों व अन्य सार्वजनिक संस्थानों में सफाई की जाएगी। पहली अक्तूबर का दिन श्रेष्ठ स्वच्छता के रूप में मनाया जाएगा और गन्दगी वाले स्थानों पर सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा राज्य के स्थानीय निकायों को भेज दी गई है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 12 जुलाई, 2017 को सभी शहरी निकायों में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इस पहले चरण का यह अभियान प्रदेश भर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और इसका समापन 23 सितम्बर, 2017 को शिमला में होना है।

फारका ने हिमाचल प्रदेश को साफ-सुथरा बनाने के लिए विशेषकर पखवाड़े के दौरान आम जनमानस, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, बच्चों, खिलाड़ियों, चुने हुए प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थानों से स्वच्छता अभियान में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की है।

नि:शुल्क दवाइयों को 71 करोड़ का बजट:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के साथ पीटरहॉफ से पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चम्बा तथा डॉ. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन की ऑनलाईन आधारशिलाएं रखी। उन्होंने वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, नागरिक अस्पताल नूरपुर, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, नागरिक अस्पताल सुन्दरनगर, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर व जिला अस्पताल सोलन की मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य शाखाओं की भी आधारशिलाएं रखी।

इसके अलावा, टांडा मेडिकल कॉलेज में जीएनएम प्रशिक्षण स्कूल की आधारशिला रखी तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मंडी में टर्शीयरी कैंसर उपचार केन्द्र तथा बिलासपुर के घुमारवीं के नागरिक अस्पताल के इंडोर खण्ड की भी आधारशिलाएं रखीं। चम्बा तथा नाहन दो मेडिकल कॉलेजों पर कुल 452 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

मातत्वृ एवं शिशु स्वास्थ्य शाखाओं की स्थापना का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन शाखाओं में ऑप्रेशन थियेटर, लेबर रूम, आईसीयू, न्यू बोर्न केयर यूनिट तथा प्रसवपूर्व व प्रसव उपरांत खण्ड और बच्चों के लिए प्रारंभिक उपचार केन्द्र होंगे।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य शाखाओं के अन्तर्गत सात स्वास्थ्य संस्थानों में 550 बिस्तरों के लिए 112 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में 200 बिस्तर, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में 100 बिस्तरों की सुविधा के अलावा नागरिक अस्पताल नूरपुर, डॉ. वाई.एस. परमार, नागरिक अस्पताल सुन्दरनगर, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर तथा सोलन प्रत्येक में 50 बिस्तरों की सुविधा होगी।

बिलासपुर जिला के नागरिक अस्पताल घुमारवीं में 50 बिस्तरों के इंडोर खण्ड के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मंडी में कैंसर उपचार केन्द्र पर 45 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएंगी। इस केन्द्र में रेडियो थैरेपी जैसी सुविधाएं होंगी और कैंसर का उपचार भी किया जाएगा, जिसमें कैंसर का पता लगाना, निदान, उपचार, उपचार के उपरांत की स्थिति, देखभाल और पुनर्वास जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में स्थापित किए जाने वाले जीएनएम प्रशिक्षण स्कूल के लिए 12.55 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में इंदिरा गांधी नि:शुल्क औषधि योजना के अन्तर्गत मरीजों को 330 नि:शुल्क दवाईयां तथा उपभोग्य वस्तुएं प्रदान करने के लिए 71 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में रूबैला खसरा टीकाकरण अभियान बड़े पैमाने पर चलाया गया है और 20 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 30 अगस्त से आरम्भ किए गए इस अभियान के अन्तर्गत अभी तक 13 दिनों में 13 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है।

योग्य उम्मीदवारों को ही मिलेंगे टिकट:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुल्लू जिला के विधानसभा क्षेत्र बंजार के सैंज में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग पार्टी के बजाए व्यक्ति विशेष के प्रति वफादार हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के समय की कांग्रेस और स्वतंत्रता उपरांत की कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आजकल जो लोग चापलूसी करते हैं, उन्हें चुनावों की अवधारणा को भुलाकर उच्च पदों पर बिठाया तथा मनोनीत किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी एक मजबूत पार्टी है, लेकिन कुछ बदलाव समय की मांग है और जितना जल्द हो सके, पार्टी के भविष्य के लिए यह बदलाव बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले, पार्टी अध्यक्ष और यहां तक की सदस्य खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर से चुनकर आते थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समितियों तथा कार्यकारी समितियों के अध्यक्ष के लिए चुनाव होते थे, लेकिन अब यह प्रथा समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें हि.प्र. कांग्रेस समिति का राज्य अध्यक्ष चुना गया था, उन्होंने स्वयं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के उच्च पदों के लिए मतदान किया है।

उन्होंने कहा कि जो किसी बैनर तले अचानक उभरे हैं, उनके लिए टिकट मुद्दा नहीं हो सकता। 'मैं पार्टी के अंदर और बाहर सभी को जानता हूं'। उन्होंने कहा कि केवल योग्य उम्मीदवारों को ही टिकट दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता हूं, जो चापलूसी करते हैं और यह मैंने अपने पूर्वजों से सीखा है।

इससे पूर्व, बजौरा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वंय सक्रिय राजनीति से सन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि वह उनका नेतृत्व करें और चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री कर्ण सिंह द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा किया जाएगा।

ढली बाई-पास पर बनेगा 7 करोड में हैलीपोर्ट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला के समीप ढली बाईपास सड़क पर हेलिपोर्ट की आधारशिला रखी। इसके निर्माण पर 7 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हैलीपोर्ट में दो हैलीकॉप्टरों के उतरने की सुविधा होगी।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हैलीपोर्ट से राज्य में और अधिक पर्यटन प्रोत्साहित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है और सड़कों की उपयुक्त मुरम्मत की जा रही है ताकि आम लोगों तथा पर्यटकों को आवागमन की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये पर्यटक गन्तव्यों को विकसित किया जा रहा है और मूलभूत सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। उन्होंने थरमाटी कैंची (फागू) में सब्जी मण्डी की आधारशिला रखी।

उन्होंने चियोग बाईपास सड़क की भी आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर सब्जी मण्डियां खोल रही है ताकि किसानों व बागवानों को उनके उत्पाद सब्जी मण्डियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें वाजिब दाम मिल सके। मुख्यमंत्री ने चियोग के तुंगेश में राजकीय डिग्री कॉलेज का लोकार्पण किया और इस कालेज को सरकार के नियंत्रण में लिया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चियोग के विज्ञान खण्ड का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक बच्चे को घर-द्वार के समीप उच्च शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कालेज खोले जा रहे हैं तथा

स्कूलों को स्तरोन्नत किया जा रहा है। परिणामस्वरूप राज्य की साक्षरता दर आज बढ़ कर 88 प्रतिशत हो चुकी है। उन्होंने ग्राम पंचायत सतोग के कौंती में कौंतीपुल का लोकार्पण किया।

रोहडू विधानसभा क्षेत्र के लिये 116 करोड़ की विकास परियोजनाएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिले के विधानसभा क्षेत्र रोहडू के दूरदराज क्षेत्र डोडरा-क्वार, चिड़गांव तथा रोहडू क्षेत्रों में 116 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किए तथा आधारशिलाएं रखी। खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री क्वार हवाई अड्डे पर नहीं उतर सके। उन्होंने दूरभाष के माध्यम से क्वार में 6.40 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की आधारशिला की घोषणा की। उन्होंने 3.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले गोसान्गो पुल तथा दूरभाष से क्वार में नागरिक अस्पताल के शुभारंभ की घोषणा की।

इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने चिड़गांव में 2.34 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बस अड्डे का लोकार्पण किया।

उन्होंने 4.69 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोन्सारी के अतिरिक्त खण्ड की आधारशिला रखी, जांगला में उप-तहसील कार्यालय खोलने की रस्म अदा की, 3.48 करोड़ रुपये की लागत की झलवाड़ी से बमवाड़ी सड़क के निर्माण के लिये भूमि पूजन सहित 3.59 करोड़ की लागत से बनने वाली भमवारी से मनघारा सड़क, 3 करोड़ रुपये की लागत की गड़सारी से खरशाली सडक, 3.68 करोड़ रुपये की सन्दासु से तेलगा सड़क, 4.14 करोड़ रुपये की आन्धा-धगोली-गांवसारी सड़क, 4.54 करोड़ रुपये की चिड़गांव-गुशाली-रोहाल सड़क, 3.34 करोड़ रुपये की सुंडली से सिन्दासली सड़क, 4.30 करोड़ की चिलाला-डुगियानी-झकनोटी सड़क, 6.61 करोड़ रुपये की जांगला से थली सड़क, 4.60 करोड़ रुपये की टांगणू से जांगलिक सड़क, 10.66 करोड़ रुपये की टिक्करी से टांगणू सड़क तथा 7.19 करोड़ रुपये की काशाधार से ढाकगांव सडक के निर्माण के लिये भूमि पूजन किये। इसके अलावा, 3.11 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले स्नातकोत्तर कालेज सीमा के बहुउद्देशीय सभागार की भी आधारशिला रखी

उन्होंने रनोल में 28 लाख रुपये की लागत से निर्मित वन विभाग के विश्राम गृह का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने 10.34 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित रोहडू बस अड्डे का लोकार्पण किया।

इसके उपरांत, मुख्यमंत्री ने रोहडू से विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण किए तथा आधारशिलाएं रखी। इनमें ग्राम पंचायत करालश में 3.39 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालसा, 3.76 करोड़ रुपये की मंचारा से बागी सड़क, 2.33 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली शरोग से भाली सड़क, 2.98 करोड़ रुपये की बरासली-कैंची-रूण्डा-झालटू सड़क, 2.69 करोड़ रुपये की गांव पेखाधार के लिये संपर्क सड़क, 1.83 करोड़ रुपये की भराल से भरोली सड़क निर्माण के लिये भूमि पूजन की रस्में अदा की। उन्होंने 7.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज रोहडू के अतिरिक्त शैक्षणिक खण्ड की भी आधारशिला रखी।

लोक निर्माण विभाग की ये परियोजनाएं लगभग 107 करोड़ रुपये की हैं। मुख्यमंत्री ने 1.45 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित उठाऊ जलापूर्ति योजना करछाड़ी तथा कटलाह का लोकार्पण किया। यह परियोजना क्षेत्र की 14 बस्तियों की लगभग 2700 की आबादी को लाभान्वित करेगी।

उन्होंने नागरिक अस्पताल रामपुर के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए।

मतदाता सूचियों में 78033 नये मतदाता शामिल

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के समस्त विधासभा क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्य प्रथम जनवरी, 2017 की अहर्ता तिथि के आधार पर पूरा कर लिया गया है। 15 सितम्बर, 2017 को फोटोयुक्त मतदाता सूची को अन्तिम रूप में प्रकाशित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त 68 विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 48,27,644 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। पुनरीक्षण के दौरान कुल 1, लाख 25 हजार 556 नए मतदाता पंजीकृत किए गए। 18-19 आयु वर्ग में 40 हजार 567 तथा 19 प्लस आयु वर्ग में 84 हजार 989 नए मतदाताओं के नाम दर्ज हुए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि 47 हजार 523 मतदाताओं के नाम मृत्यु/स्थान परिवर्तन/ दोहरे पंजीकरण आदि के कारण मतदाता सूचियों से हटाए गए है। इस प्रकार मतदाता सूचियों में कुल 78 हजार 33 मतदाताओं की बढ़ौतरी हुई है, जो कि प्रारूप में प्रकाशित मतदाताओं पर 1.62 प्रतिशत की बढ़ौतरी है।

उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कुल 49,05,677 मतदाता पंजीकृत है जिनमें 24 लाख 98 हजार 174 पुरूष तथा 24 लाख 7 हजार 503 महिलाएं है। पुनरीक्षण के दौरान मतदाता जनसंख्या अनुपात 654 से बड़कर 664 हो गया है। प्रदेश में सबसे अधिक मतदाता सुलह निर्वाचन क्षेत्र में 92,753 तथा सबसे कम लाहौल व स्पिति निर्वाचन क्षेत्र में 22,849 मतदाता है।

प्रवक्ता ने कहा कि अन्तिम रूप में मतदाता सूची सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एडीएम/एसडीएम), सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में अथवा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ लेबल अधिकारियों के पास निरीक्षण के नि:शुल्क उपलब्ध है।

इसके अलावा, राज्यों के समस्त विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग की वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर भी उपलब्ध है। सूचियों में दर्ज नामों की पुष्टि उपरोक्त वैबसाईट से भी की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति इन मतदाता सूचियों की पीडीएफ फायलों की सीडी 100 रूपये प्रति सीडी की दर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश शिमला के कार्यालय या सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

1,15,47,151 सेब की पेटियां भेजी मण्डियों को

शिमला/शैल। बागवानी विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान सेब सीजन के दौरान राज्य के विभिन्न भागों से अभी कुल 1,15,47,151 सेब की पेटियां देश की विभिन्न मण्डियों में भेजी जा चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि अभी तक एचपीएमसी तथा हिमफैड द्वारा कुल 271 सेब एकत्रण केन्द्रों के माध्यम से मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत कुल 11,629 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई है।

प्रवक्ता ने कहा कि सेब के विपणन का कार्य सुचारू ढंग से जारी है और राज्य के किसी भी भाग में ट्रकों की कोई कमी नहीं है।

आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुःख ही देता है.....चाणक्य

सम्पादकीय

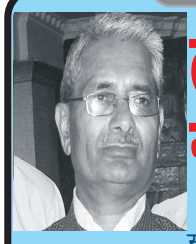

तेल कीमतों से फिर उठे नीयत और नीति पर सवाल

पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से केन्द्र सरकार के फैसलों को लेकर एक बार फिर वैसी ही बहस छिड़ गयी है जो नोटबंदी के फैसले के बाद उभरी थी। यह बहस इसलिये उठी है क्योंकि पिछले तीन वर्षो की तुलना में यह कीमतें अपने उच्चतम स्तर तक पहुच गयी हैं। जबकि 2014 में जब मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी और उस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की जो कीमत थी उसके मुकाबले में आज 2017 में इस कीमत में 58% की कमी आयी है। अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार की कीमतों को सामने रखते हुए तो पेट्रोल-डीजल की कीमत आधी रह जानी चाहिये थी लेकिन ऐसा न होकर यह अपने उच्चतम पर पहुंच गयी। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि सरकार ने एक्साईज ड्यूटी बढ़ा दी। 2014 में डीजल पर 3.56 रूपये ड्यूटी थी जो अब 17.33 रूपये हो गयी है। पेट्रोल पर यह एक्साईज डूयटी 9.48 रूपये थी जो आज 21.48 रूपये कर दी गयी है। इन तीन वर्षो में यह डूयटी 11 बार बढ़ी है और स्वभाविक है कि जब एक्साईज डयूटी बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेगी ही। लेकिन ईधन का सबसे बड़ा स्त्रोत तेल है और माल ढुलाई का सबसे बड़ा कारक है। इसलिये जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो परिणामस्वरूप हर चीज की कीमत बढ़ जायेगी। इसी कारण से इन तीन वर्षो में सारे आंकड़ों और दावों के वाबजूद मंहगाई लगातार बढ़ती ही गयी है। यह तेल की कीमतें बढ़ने का जो तर्क सरकार दे रही है कि एक्साईज डयूटी से मिलने वाला पैसा जन कल्याण की योजनाओं पर खर्च होता है और हर चीज पर जन संख्या के एक बड़े वर्ग को जो सब्सिडी दी जा रही है। उसके लिये भी पैसा कहीं से तो आना है। इस परिदृश्य में सरकार के कीमतें बढ़ाने के फैसले को गल्त नही ठहराया जा सकता।

लेकिन जब इसी के साथ जुड़े दूसरे यह पक्ष सामने आते हैं कि सरकार के इन फैसलों का लाभ आम आदमी की बजाये कुछ उद्योग घरानों को ज्यादा हो रहा है तो सरकार की नीयत और नीति दोनों पर संदेह होने लगता है। क्योंकि जब सरकार के बड़े फैसलों पर नजर जाती है तब सबसे पहले डिजिटल इण्डिया का नारा सामने आता हैं परन्तु डिजिटल इण्डिया का अगुआ सरकार के उपक्रम बीएसएनएल या एमटीएनएल न बनकर रिलांयस 'जियो' बना। कैशलैस इकोनॉमी का लीडर एनपीसीआई के ''रूपये '' की जगह ''पेटीएम'' हो गया। फ्रांस के राफेल जेट का भागीदार हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स के स्थान पर रिलांयस का ''पिपावा डिफैंस'' हो गया। भारतीय रेल को डीजल की सप्लाई का ठेका इण्यिन ऑयल कारपोरेशन की जगह रिलांयस पैट्रोकेमिकल्स को मिल गया। आस्ट्रेलिया की खानों का टैण्डर सरकार चाहती तो सरकारी उपक्रम एमएमटीसी को एसबीआई की बैंक गारंटी पर मिल सकता था। लेकिन यह अदानी ग्रुप को मिला। इन कुछ फैसलों से यह गंध आती है कि क्या जानबूझकर सरकारी उपक्रमों को एक योजनाबद्ध तरीके से निज़िक्षेत्र का पिछलगू बनाया जा रहा है । क्योंकि जब निजिक्षेत्र को इस तरह के लाभ पहुंचाये जाते है तो उनसे बदले में पार्टीयों को चुनावी चंदा मिल जाता है जो सरकारी उपक्रमों से संभव नही हो सकता। और इससे आम आदमी तथा सरकार दोनों का नुकसान होता है। यदि निजिक्षेत्र की जगह सरकारी उपक्रमों को आगे बढ़ाया जायेगा तो इससे सीधा लाभ सरकार को होगा। जो लाभ रिलांयस और अदानी ग्रुप को दे दिये गये हैं यदि यही लाभ सरकारी क्षेत्र को मिलते तो एक्साईज डूयटी बढ़ाकर तेल की कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता नही पड़ती।

आज आम आदमी काफी जागरूक हो चुका है वह सरकार के फैसलों को समझने लगा है। उसे जो अच्छे दिन आने का सपना दिखाया गया था वह अब पूरी तरह टूट गया है क्योंकि उसके लिये अच्छे दिनों का एक ही व्यहारिक मानक है कि मंहगाई कितनी कम हुई है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हर चीज को आधार से लिंक कर दिया गया है। उसे क्या खाना और पहनना चाहिये यह तय करना सरकार का काम नही है। सरकार का काम है एक सुचारू व्यवस्था स्थापित करना और वह अभी तक हो नही पायी है। क्योंकि हर फैंसला कहीं-ना कहीं आकर विवादित होता जा रहा है। जिस आधार लिंककिंग पर इतना जोर दिया गया उस आधार को लेकर सर्वोच्च अदालत ने जो प्रश्न उठाये है उससे पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। नोटबंदी के फैसले से लाभ होने की बजाये नुकसान हुआ है क्योंकि जब पुराने नोट वापिस लेकर उनके बदले में नये नोट वापिस देने पड़े हे तो इस फैसले का सारा घोषित आधार ही धराशायी हो जाता है। नोटबंदी के बाद अब जीएसटी लाया गया। ''एक देश एक टैक्स'' का नारा दिया गया लेकिन इस फैसले के बाद चीजो की कीमतों में कमी आने की बजाये और बढ़ी है क्योंकि टैक्स की दर बढ़ा दी गयी जो पहले अधिकतम 15% प्रस्तावित थी उसे 28% कर दिया गया। यह टैक्स कहां किस चीज पर कितना है इसको लेकर न तो दुकानदार को और न ही उपभोक्ता को पूरी जानकारी दी गयी है क्योंकि इसे लागू करने वाला तन्त्र स्वयं ही इस पर स्पष्ट नही है। सरकार के सारे महत्वपूर्ण फैसलों पर यही धारणा बनती जा रही है कि जिस तेजी से यह फैसले लाये जा रहे हैं उनके लिये उसी अनुपात में वातावरण तैयार नही किया जा रहा है। यह नही देखा जा रहा है कि इनका व्यवहारिक पक्ष क्या है। बल्कि यह गंध आ रही है कि यह फैसले कुछ उन उद्योग घरानों को सामने रखकर लिये जा रहे हैं जिन्होने पिछले चुनावों के प्रचार अभियान में मोदी जी को विशेष सहयोग प्रदान किया था। लेकिन देश केवल कुछ उद्योग घराने ही नही है और आम आदमी इसे अब समझने लगा है।

पंचायती राज संस्थानों के सुदृढ़ीकरण में अग्रणी हिमाचल

ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थानों के महत्व को स्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिये अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान है और आज राज्य देश में आदर्श राज्य बनकर उभरा है। महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है और राज्य में पहले ही उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को क्रियान्वित किया है। यह शुभ संकेत है कि इस पहाड़ी प्रदेश में 58 प्रतिशत पंचायती राज संस्थानों में महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है, जबकि अन्य राज्यों में इस वर्ग को अभी भी 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हो रही है।

पंचायती राज प्रणाली को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने इन संस्थानों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, पर्याप्त स्टॉफ तथा नियमित प्रशिक्षण के अलावा ग्राम पंचायतों को कुशल तरीके से कार्य करने के लिये कंप्यूटर व इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की है।

राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर हार्डवेयर प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज विभाग ने समस्त पंचायती राज संस्थानों के कंप्यूट्रीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया है, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा जिम्मेवारी सुनिश्चित हुई है। विभाग ने पंचायती राज संस्थानों के लेखा और अभिलेखों की उपयुक्त देखभाल भी सुनिश्चित की है। लोगों को ग्राम पंचायतों के माध्यमों से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की 400 रिक्त पद भरे हैं। राज्य सरकार ने पंचायत सहायकों के 200 और पद भरने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थानों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न श्रेणियों के 33 पद सृजित किए हैं।

राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां को आयोजित करवाने के लिए 48.06 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 226 पंचायत घरों के जीर्णोद्धार के लिए 7.42 करोड़ रुपये, नई पंचायत घरों के निर्माण के लिए 750 रुपये शामिल हैं।

राज्य सरकार ने शिमला के मशोबरा में राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र के निर्माण के लिए 1.25 करोड़ रुपये, 13 खंड स्तरीय संसाधन केन्द्रों के निर्माण के लिए 1.56 करोड़ रुपये तथा मंडी, सोलन, हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा, किन्नौर तथा बिलासपुर जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के निर्माण के लिए प्रत्येक को 2.50 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थान बैजनाथ के विकास के लिए 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

भारत सरकार की ई-पंचायत परियोजना के अन्तर्गत 11 प्रस्तावित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में से 7 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों को पंचायती राज संस्थानों में आरम्भ कर दिए हैं। इन एप्लीकेशनों के लिए पंचायतों/विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन पंचायती राज संस्थान मशोबरा में किया जा रहा है। पंचायत राज संस्थानों में इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों पर कार्य आरम्भ हो चुका है। पंचायतों को आवारा पशुओं से मुक्त करने के लिए हर खंड में दो श्रेष्ठ पंचायतों को पुरस्कृत करने की योजना की अधिसूचना की गई है जिसमें श्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार राशि के लिए 7.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रो में महिलाओं के सशक्तिकरण विशेषकर महिलाओं व बच्चों से जुड़े मुददों तथा पंचायतों के समग्र विकास से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा करने के लिए निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में प्रत्येक ग्राम सभा में दो महिला ग्राम सभाएं आयोजित करने का प्रावधान किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रथम सभा 8 मार्च तथा द्वितीय सभा सितम्बर महीने के प्रथम रविवार को आयेजित की जाएगी।

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के चयनित प्रतिनिधियों का मानदेय 1 जुलाई, 2017 से बढ़ाया गया है। पंचायत सहायकों का मानदेय 5910 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये तथा सिलाई शिक्षक का मानदेय 2300 रुपये से बढ़ाकर 2600 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसके अतिरिक्त दो सहायक इंजिनियर, 172 जुनियर इंजिनियर, 12 जुनियर स्केल स्टेनोग्राफर, 1297 पंचायत सचिवों तथा 10 जुनियर एकाउंटेट को नियमित किया गया है।

ग्राम सभा बैठकों विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित बनाने के तहत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। संशोधन के अनुसार ग्राम सभा बैठकें जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर माह में इस ढंग से आयोजित की जाएंगी ताकि इन महिनों में जिले की सभी पंचायतों में सभाएं सुनिश्चित हो सकें। कार्यसंख्या (कोरम) पूरी न होने के कारण पंचायतों के विकास में कमी न आए इसलिए ग्राम सभा की साधारण बैठक की कार्यसंख्या को एक तिहाई से घटाकर एक चौथाई किया गया है।

भारत लड़ रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई

वी.श्रीनिवास

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, एक स्वतंत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, लोकपाल एवं लोक आयुक्त अधिनियम 2013, व्हिसल ब्लोअर्स सुरक्षा अधिनियम 2011, काला धन एवं मनीलॉड्रिंग निरोधक अधिनियम, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम सहित एक मजबूत और समय समय पर आजमाए गए संस्थागत एवं विधायी ढांचे के नेतृत्व में लड़ी जाती है जिसमें अपराधीकरण तथा रिश्वतखोरी से संबंधित कई सारे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों यानी लोक सेवकों को वार्षिक आधार पर अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रत्येक चुनाव चक्र के दौरान अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है।

भारत के 'अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता' के दृष्टिकोण एवं साथ ही, 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण का परिणाम हाल के वर्षों में शासन के म डल को सरल बनाये जाने के रूप में सामने आया है। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में शासकीय कर्मचारियों द्वारा प्रमाण पत्र जमा किए जाने के लिए प्रमाणन/प्रमाणीकरण प्रणाली को समाप्त किया जाना, निम्न स्तर के पदों पर भर्ती के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार की आवश्यकता को समाप्त करना तथा 50 वर्ष से अधिक उम्र के अक्षम तथा संदिग्ध आचरण वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति समय से पूर्व ही सेवा से हटा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने काले धन एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उच्च मूल्य वाली करेंसी को विमुद्रित कर दिया। काले धन से लड़ने के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। सरकार ने कोयला ब्लॉकों के लिए ऑनलाइन नीलामी का भी संचालन किया। सरकार ने यूरोप एवं कर छूट (टैक्स हेवेन्स) प्राप्त अन्य देशों में कर छूट की प्रणाली को समाप्त करने के लिए जी-20 की बैठकों में अंतराष्ट्रीय सहयोग की भी मांग की। स्विस अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भारत ने कहा है कि काले धन एवं कर वंचना के प्रकोप से मुकाबला करना दोनों ही देशों के लिए एक 'साझा प्राथमिकता' है।

झारखंड की अपनी हाल की एक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड में सखी मंडलों (स्वयं सहायता समूहों) को उपहारस्वरूप कुछ स्मार्ट फोन भेंट किए और उन्होंने कहा कि स्मार्ट फोन के उपयोग के बारे में ग्राम वासियों से उन्हें जो उत्तर सुनने को मिला, उसे सुन कर वे दंग रह गए। 'सरकार को और अधिक स्मार्ट बनाने' पर भारत का फोकस भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई का सबसे अग्रणी हिस्सा रहा है। उसी मात्रा में सब्सिडी दिए जाने का लाभ मैनुअल प्रणाली की तुलना में एक 'स्मार्ट शासन म डल' में अधिक प्रभावी तरीके से प्रदान किया जा सकता है।

जन धन योजना ने ओवरड्रॉफ्ट सुविधा के साथ बैंकिंग खातों तक सार्वभौमिक एवं स्पष्ट पहुंच उपलब्ध कराई। 2016 में, वित्तीय एवं अन्य सब्सिडियों, लाभों तथा सेवाओं की लक्षित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आधार अधिनियम प्रख्यापित किया गया। इस अधिनियम में आधार पहचान संख्याओं को निर्दिष्ट किए जाने के जरिये व्यक्तियों को सब्सिडियों की कारगर, पारदर्शी एवं लक्षित प्रदायगी उपलब्ध कराई गई।

सरकार द्वारा उठाया गया तीसरा अहम कदम भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) को लागू करना था जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप्लीकेशन है। भीम ऐप्लीकेशन बैंकों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करता है और इसका उपयोग सभी मोबाइल उपकरणों पर किया जा सकता है। सामूहिक रूप से मिल कर जन धन योजना-आधार अधिनियम और भीम ऐप्लीकेशन ने एक स्मार्ट गवर्नमेंट उपलब्ध कराया है जहां सब्सिडी प्रवाह समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से लाभार्थी तक पहुंच जाता है।

सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से निवारक सतर्कता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। सीबीसी द्वारा कई निवारक सर्तकता उपाय लागू किए गए हैं। गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) जैसे उपायों ने सार्वजनिक खरीद में जवाबदेही एवं शुद्धता को बेहतर बनाने में मदद की है। आयोग ने छात्रों एवं युवाओं की शिक्षा के जरिये आचार नीति को बढ़ावा देने, सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाने, लोक सेवकों के अधिकार एवं उनसे अंतःसंपर्क को कम करने के जरिये प्रक्रिया को सरल बनाने, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने तथा निवारण उत्पन्न करने के लिए साबित गलत आचरण के सभी मामलों में कठोर सजा प्रदान करने का प्रयास किया है। सीवीसी ने ई-संकल्प, जिसे नागरिकों एवं संगठनों द्वारा स्वेच्छा से लिया जाएगा, के जरिये भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन उत्पन्न करने का प्रयास किया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने लेखा परीक्षण एवं लेखांकन प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। वित्तीय शासन के क्षेत्र में लागू कुछ बड़े बदलावों में रेल बजट एवं आम बजट का एकीकरण, योजना एवं गैर योजना व्ययों का विलय, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कई क्षेत्रों को खोलना एवं वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू करना शामिल है। शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को फंड के प्रवाह की विशालता को देखते हुए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उनके लेखा परीक्षण की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की है। सीएजी ने टैक्स फाइलिंग, आकलन तथा वसूली प्रक्रियाओं के बढ़ते ऑटोमेशन से उत्पन्न डिजिटल सूचना की बड़ी मात्रा पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

सरकार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम एक अधिकार आधारित कानून है जिसने राष्ट्र के प्रशासन में नागरिकों के लिए एक स्थायी हिस्सेदारी का सृजन किया है। आरटीआई अधिनियम की वजह से शासन में बेहतरी आई है। सूचनाओं को साझा करने के जरिये, नागरिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया के हिस्से बन गए हैं जिसकी वजह से नागरिकों तथा सरकार के बीच भरोसा पैदा होता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के संबंधित कानून को मजबूत बनाने का एक कानून है। इस कानून में आधिकारिक कार्यों के संबंध में कानूनी पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त परितोषण लेने पर दंड देने का प्रावधान है। इसकी जांच से सबंधित अधिकारी सीबीआई एवं राज्य पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि लोक सेवकों के लिए जवाबदेही के मानकों को वास्तविक स्तर पर रखा जाना चाहिए जिससे कि अधिकारी गणों को ईमानदार निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट न हो सके।

देश में व्हिसल ब्लोअर्स को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 2015 में व्हिसल ब्लोअर्स अधिनियम में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं पर ध्यान दिया गया है और खुलासों, जो देश की संप्रभुता और अखंडता को पूर्वाग्रह पूर्ण तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, के खिलाफ सुरक्षापायों को मजबूत बनाया गया है। बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 को मजबूत बनाने के लिए उसमें संशोधन किया गया जिससे कि आय कर अधिकारियों को बेनामी संपत्तियों को संलग्न करने तथा जब्त करने के लिए अधिकारसंपन्न बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, अगर कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा बेनामी लेनेदेन के अपराध के मामले में दोषी पाया गया तो उसे सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी तथा उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इस संशोधित कानून के अस्तित्व में आने के बाद से कई बेनामी संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है।

निष्कर्ष के रूप में, ऐसा कहा जा सकता है कि भारत भ्रष्टाचार एवं काले धन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ ही रहा है। स्मार्ट शासन पर ध्यान केंद्रित किए जाने के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं।

राजभाषा दर्जे से आगे हिन्दी

प्रियदर्शी दत्ता

14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1949 में इसी तारीख को संविधान सभा ने एक लंबी और सजीव बहस के बाद देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया था। भारतीय संविधान के भाग XVII के अनुच्छेद 343 से 351 तक इसी विषय के बारे में है। अनुच्छेद 343 (1) में यह घोषणा की गई है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। लेकिन अनुच्छेद 343 (2) और उसके बाद के अनुच्छेदों को पढ़ने से पता चलता है कि भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में राजभाषा के मुद्दे को बहुत कठिन और जटिल रास्ते से होकर गुजरना है क्योंकि देश के सरकारी संस्थानों में अंग्रेजी में निर्धारित कानूनों, नियमों और विनियमों का ही वर्चस्व है।

इसका एक समझौता के रूप में वर्णन किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां, संसद और राज्य विधानसभाओं में पेश किए जाने वाले या पारित सभी विधेयकों और अधिनियमों के अधिकृत पाठ, संविधान के तहत पारित सभी आदेश/नियम /कानून और विनियमों को अंग्रेजी में ही होना चाहिए (जैसा औपनिवेशिक भारत में था) 17 फरवरी, 1987 को संविधान (58वां) संशोधन अधिनियम के पारित होने तक संविधान (संशोधनों में शामिल) का कोई अद्यतन संस्करण संशोधनों के साथ हिंदी में जारी नहीं किया जा सकता था। विभिन्न कारणों से एक राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। यही कारण है कि 70 वर्षों के बाद भी हिन्दी अंग्रेजी की जगह लेती हुई कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस कार्य के लिए केवल 15 साल का समय दिया था।

राजभाषा की अवधारणा राज्य के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सशस्त्र बलों आदि से संबंधित है। हालांकि, देश अपने सरकारी संस्थानों से कहीं बड़ा है। भारत में महात्मा गांधी ने जो जन जागरण किया वह संस्थानों से बाहर हुआ था। उनका असहयोग आंदोलन या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कांग्रेस का चुनाव में भाग लेने के उनके विरोध से यह पता चलता है कि उन्होंने देश की अपने संस्थानों पर निर्भरता को नकार दिया था। गांधीजी औपनिवेशिक भारत में उसके राज्य तंत्र के बीच की खाई और उसके लाखों लोगों के बारे में पूरी तरह जागरूक थे। वे भारत की बजाये भारतीय राष्ट्र को संबोधित करना चाहते थे। गांधीजी ने ऐसा करने के लिए अंग्रेजी की बजाये लोगों की भाषा का उपयोग करने का तरीका अपनाया।

भाषा का यह प्रश्न गांधीजी के स्वदेशी अभियान का अभिन्न अंग था। उन्होंने यह समझ लिया था कि लोग अपनी भाषा के जरिये ही स्वराज के मिशन में शामिल हो सकते हैं। इसलिए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, गांधी ने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया। प्रताप (हिन्दी) में 28 मई, 1917 को प्रकाशित उनके लेख में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने की वकालत की गई थी।

इसमें उन्होंने कहा था कि ज्यादातर भारतीय, जिन्हें न तो हिंदी आती है और न ही अंग्रेजी, उनके लिए हिन्दी सीखना अधिक आसान होगा। उन्होंने कहा कि केवल डरपोक होने के कारण ही भारतीयों ने अपना राष्ट्रीय कार्य व्यापार हिंदी में करना शुरू नहीं किया है। अगर भारतीयों इस कायरता को छोड़ दे और हिंदी में विश्वास जताएं तो राष्ट्रीय और प्रांतीय परिषदों का कार्य भी इस भाषा में किया जा सकता है।

इसी लेख में गांधीजी ने पहली बार दक्षिण भारत में हिंदी मिशनरियों को भेजने का विचार प्रस्तुत किया। उन्हीं के विचार से 1923 में स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के रूप में मूर्त रूप लिया। 20 अक्टूबर 1917 को भरूच में दूसरे गुजरात शिक्षा सम्मेलन में दिया गांधीजी का भाषण महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस भाषण में उन्होंने हिंदी को लोकप्रिय बनाने में स्वामी दयानंद सरस्वती के अग्रणी प्रयासों की सराहना की।

स्वामी दयानंद (1824-1883) गांधीजी की तरह ही गुजरात के रहने वाले थे। वे धार्मिक बहस और शिक्षण के माध्यम के तौर पर संस्कृत का उपयोग करते थे। हिमालय क्षेत्र और उत्तर भारत में दशकों तक रहने के बावजूद उन्होंने कभी भी हिंदी सीखने का प्रयास नहीं किया। लेकिन 1873 में, जब वे कोलकाता की यात्रा पर गए, तो उनकी भेंट ब्रह्म समाज के केशब चन्द्र सेन से हुई। सेन ने उन्हें सलाह दी कि वे जनता तक पहुंच बनाने के लिए संस्कृत की जगह हिंदी का उपयोग करें। दिलचस्प बात यह है कि स्वामी दयानंद और केशव चन्द्र सेन दोनों में से कोई भी मूल रूप से हिंदी भाषी नहीं था। उन्होंने इस मैत्रीपूर्ण परामर्श को स्वीकार कर लिया और थोड़े ही समय में हिंदी में महारत हासिल कर ली। उन्होंने अपनी महान कृति सत्यार्थ प्रकाश (1875) की रचना भी हिंदी में ही की। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने की सशक्त एजेंसी के रूप में कार्य किया।

इस प्रकार गांधीजी ने हिंदी की मशाल उस जगह से अपने हाथ में थामी, जहां स्वामी दयानंद ने उसे छोड़ा था। जहां एक ओर स्वामी दयानंद का मिशन धार्मिक था, वहीं दूसरी ओर गांधीजी का मिशन राष्ट्रीय था। गांधीजी ने हिंदी को भारतीय मानस को 'उपनिवेशवाद से मुक्त' कराने के साधन के रूप में देखा। हिंदी को लोकप्रिय बनाने के उनके मिशन को दक्षिण भारत में कई लोगों ने आगे बढ़ाया।

जी. दुर्गाबाई (1909-1981) जो आगे चलकर संविधान सभा की सदस्य भी बनीं, ने किशोरावस्था में काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), में लोकप्रिय बालिका हिंदी पाठशाला का संचालन किया। बालिका हिंदी पाठशाला का दौरा करने वालों में सी.आर. दास, कस्तूरबा गांधी, मौलाना शौकत अली, जमना लाल बजाज और सी.एफ. एंड्रयूज शामिल थे। वे यह देखकर हैरत में पड़ गये कि कुछ सौ महिलाओं को हिंदी का ज्ञान प्रदान करने वाली पाठशाला का संचालन एक किशोरी द्वारा किया जा रहा है।

लेकिन दुर्गाबाई के संविधान सभा तक पहुंचते-पहुंचते दक्षिण भारत में हिंदी के हालात बदल चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि मूल हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी के पक्ष में जोशोखरोश से किये गये प्रचार ने अन्य भाषाओं के लोगों को बेगाना कर दिया। स्वयं सेवियों ने जो उपलब्धि हासिल की थी, उत्साही गुमराह लोग उसे नष्ट कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने 14 सितंबर, 1949 को अपने भाषण में कहा, 'इस सदी के आरंभिक वर्षों में हमने जिस उत्साह के साथ हिंदी को आगे बढ़ाया था, उसके विरुद्ध इस आंदोलन को देखकर मैं स्तब्ध हूं। उनकी ओर से बढ़चढ़कर किया जा रहा प्रचार का दुरुपयोग मेरे जैसे हिंदी का समर्थन करने वाले लोगों का समर्थन गंवाने का जिम्मेदार है और जिम्मेदार होगा।'

जी. दुर्गाबाई द्वारा अपने भाषण में जिस कशमकश की बात की है वह 70 साल बाद आज भी प्रासंगिक है। भाषा के कानूनी दर्जे को लागू करने वालों की तुलना में गैर हिंदी भाषी अपने स्वैच्छिक प्रयासों के बल पर हिंदी के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होंगे। संवर्द्धित साक्षरता तथा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सांस्कृतिक संपर्क हिंदी के उद्देश्य के लिए ज्यादा मददगार होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्मे ने हिंदी की एक विनीत चलन के रूप में सहायता की है। लक्ष्य अधिकतम लोगों तक ऐसी भाषा में पहुंच बनाने का होना चाहिए, जिसे वे समझ सकते हों।

पसूका

चुनाव आते ही चरित्र हनन की राजनीति पर अतर आती है भाजपा:वीरभद्र सिंह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऊना जिला के अम्ब में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा उनके खिलाफ बनाए गए झूठे मामलों पर हालांकि उन्हें न्यायालयों में बेवजह काफी धनराशि खर्च करनी पड़ रही है, परन्तु वह उनकी कुत्सित चालों से घबराने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि वह भाजपा के दुष्प्रचार के खिलाफ अन्त तक लड़ते रहेंगे और उनकी सभी चालों का मुँहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वह हारने वालों में नहीं है और भाजपा का उनको हराने का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि वह उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब देश की न्यायपालिका उनके खिलाफ विरोधियों द्वारा बनाए गए झूठे मामलों में उन्हें सम्मानपूर्वक बरी करेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार झूठ के पुलिन्दे के सिवा कुछ भी नहीं है। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस सरकार के विकास को टक्कर देने के लिए भाजपा चरित्रहनन की राजनीति पर उतर आई है। उनका एक ही मुद्दा होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पर झूठे आरोप लगाकर प्रहार किया जाए परन्तु यह भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अच्छे नेताओं की कोई कमी नहीं है। भाजपा उन्हें बेवजह निशाना बना रही है और वह प्रधानमंत्री और प्रदेश के भाजपा के नेताओं को यह सन्देश देना चाहते हैं कि वह उनके इस प्रकार के षडयंत्रों से डरने वाले नहीं हैं चाहे वे उनके खिलाफ कितने भी झूठे मामले बना लें।

922 करोड़ रूपये की स्वां नदी तटीकरण की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वां नदी तथा उसकी 73 सहायक नदियों के तटीकरणकार्य प्रगति पर है परन्तु धन की कमी के कारण इसमें अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होने कहा कि अनेक बार केन्द्र सरकार से आग्रह करने के बावजूद धनराशि को बेवजह रोका गया है। परियोजना के प्रथम वर्ष की लागत 330 करोड़ रूपये थी जिसके लिए राज्य को 99 करोड़ रूपये का योगदान देना था जबकि शेष राशि का वहन केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाना था। परियोजना को आरम्भ करने के समय केन्द्र सरकार द्वारा 189.351 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई और अब केन्द्र सरकार द्वारा कुछ राशि जारी की गई है।

उन्होंने इस अवसर पर नागरिक अस्पताल अम्ब को 50 बिस्तरों में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।

भारत के विकास में महिलाओं का योगदान अहम होगा–धूमल

शिमला/शैल। नादौन भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर कांगू में महिला सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पूर्व सीएम प्रो.प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित करते हुए धूमल ने कहा कि भाजपा में महिला शक्ति को उचित सम्मान दिया जाता है जिसका प्रमाण पार्टी द्वारा बूथ लेवल से लेकर केन्द्र स्तर तक महिलाओं की भागीदारी को दर्शाता है। समय के साथ नारी शक्ति आगे बढ़ी है तथा हर क्षेत्र में भारतीय नारी ने देश का गौरव बढ़ाया है। भविष्य के भारत के विकास में नारी शक्ति का योगदान समय के साथ बढ़ेगा तथा भारत के विकास में महिलाओं का योगदान अहम होगा। चूल्हे-चौके से निकलकर आज की नारी हाथ में बंदूक लिए बार्डर की रक्षा कर रही है जोकि सबके लिए सम्मान का विषय है। धूमल ने कहा कि भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों में महिलाएं अहम पदों पर आसीन हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री सहित पूरा परिवार जमानत पर है। इससे देवभूमि पूरे विश्व स्तर पर बदनाम हुई है ।

इस मौके पर प्रदेश भाजपा महिला मौर्चा अध्यक्षा इंदू गोस्वामी ने कहा कि बीते केन्द्रीय सरकार के भाजपा काल में विदेशों में भी भारत की साख बड़ी है जबकि मोदी का भी समान बड़ा है। उन्होंने कहा कि इस देश को पहले मुगलों तथा अग्रेजों बाद में कांग्रेस ने साठ साल तक महिलाओं के समान में कमी बरकरार रखी। परंतु भाजपा ने महिलाओं का समान बढ़ाकर उन्हें बराबरी का हक दिलाया है। कांग्रेस शासन काल में हुए गुडिया कांड ने प्रदेश को शर्मशार किया है। इंदू गोस्वामी ने कहा कि प्रदेश में मात्र दो ही महिला थाने शिमला व धर्मशाला में हैं यह थाने भाजपा सरकार के समय स्थापित हुए हैं कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी महिला थाना नहीं खोला अन्यथा गुडिया कांड जैसे घिनौने अपराध नहीं होते। महिलाओं ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर यह संदेश दिया है कि प्रदेश में परिवर्तन के लिए लोग एकजुट हो गए हैं और आने वाली सरकार भाजपा की होगी।

राजनीति की चपेट में अर्की का सायर मेला

अर्की/शैल। परंपराएं प्रतिभा को जन्म देती हैं और प्रतिभाएं परंपराओं की नींव रखती हैं। संस्कृति और परंपराओं पर अगर नेता गिरी व बाजारू ताकतें हावी हो जाए तो यही संस्कृति व परंपराएं समाज का अहित करना शुरू कर देती ।

जिला सोलन के अर्की में मनाए जाने वाले सायर मेले के साथ कुछ इसी तरह का हो रहा है। पिछले लंबे अरसे से इस मेले पर भाजपा व कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी व राजनीति हावी हो गई है। पब्लिक के इस मेले को इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने खुद को स्थानीय राजनीतिक पटल पर उभारने का जरिया बना डाला है। बहरहाल, सरकार ने इस मेले को जिला स्तरीय घोषित कर दिया। लेकिन पार्टियों की गुटबाजी ने इसे बदरंग करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब मेले का स्तर घट गया है।

आलम ये है कि इस बार इस मेले में मुख्य अतिथि बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जिनका नाम अर्की से विधानसभा हलके से चुनाव लड़ने के आगे किया जा रहा हैं, वो मेले में मुख्य अतिथि बनने से मुकर गए। हालांकि समझा जा रहा था कि वो मेले में आने के लिए नगर पंचायत अर्की की अध्यक्षा सावित्री गुप्ता व बाकी स्थानीय नेता राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मेले में बतौर मुख्य अतिथि बनने का न्यौता देने गए थे लेकिन उन्होंने आने से इंकार कर दिया। ऐसे में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर को मुख्य अतिथि बनाने का इंतजाम किया गया। मेले के दूसरे दिन डीसी सोलन राकेश कवंर मुख्य अतिथि होंगे।

इस मेले का मुख्य आकर्षण झोटो की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण पहले ही बंद हो गई। लोगों यहां झोटों की लड़ाई देखने की दूर-दूर से आते थे। लेकिन अब ये आकर्षण भी खत्म हो गया हैं। कायदे से तो होना ये चाहिए था कि मेले का आकर्षण बनाए रखने के लिए कुछ बेहतर चीजें की जाती । जिस तरह से कुल्लू के दशहरा मेले में दस हजार कलाकारों को एक जगह एकत्रित कर नृत्य किया व इसे गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड में शामिल कराया ।अब ये नृत्य दशहरा उत्सव के मुख्य आकर्षणों में से एक हैं। अर्की में भी कुछ ऐसा ही कुछ किया जा सकता था। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ।

स्थानीय लोगों की माने तो प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार होती हैं तो मेला कमेटी में कांग्रेस लोगों का दबदबा हो जाता हैं। इसी तरह जब भाजपा की सरकार हो तो भाजपा के लोग अपने तरीके से इंतजाम करते हैं।

जेपी कंपनी व अंबुजा जैसे कारपोरेट घरानों से फंडिंग आनी शुरू हो गई तो। स्थानीय निवासी श्याम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अब 'शो ऑफ'ज्यादा हो गया है। पहले न्यूट्रीलिटी होती थी। वो टिप्पणी करते हैं कि राजनीति, कारपोरेट घरानों ने हमारी संस्कृति व परपंराओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया है।

गिरधारी लाल शर्मा ने कहा कि मेले में राजनीति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कारपोरेट फंडिंग को लेकर वो कहते है कि बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता।

कांग्रेस नेता व नोटिफाइड एरिया कमेटी के अध्यक्ष रहे सतीश कुमार कहते है कि ये सच है कि अब कांग्रेस व भाजपा ने मेला बांटना शुरू कर दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पैसे कम थे, लेकिन मेला अपना था। अब पैसे ज्यादा आ गया है लेकिन 'शो ऑफ' ज्यादा हो गया है। हालांकि राजनीतिक लोग ही सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। लेकिन अब अपने अपने ग्रुप बन गए हैं।

उज्ज्वल योजना से देश की ढाई करोड़ महिलाओं को मिला लाभ:अनुराग ठाकुर

हमीरपुर /शैल। उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमन्त्री नरेंदर मोदी ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली देश की ढाई करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। मोदी जी के मात्र एक बार कहने पर सवा करोड़ सुविधा सम्पन्न लोगों ने गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी। मोदी सरकार आने के बाद गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खातों में आती है। फर्जी गैस खाते सामने आये और पेट्रोलियम मंत्रालय ने सतारह हजार करोड़ रुपये देश के बचाए हैं। मोदी सरकार में गैस सब्सिडी का पैसा सीधे खाते मेआने से से 54 हजार करोड़ रूपए देश के खजाने के बचाए गये हैं। हमीरपुर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण समारोह में उपस्थित जनसभा को सम्बोधित करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा मोदी सरकार ने ऐसी कई योजनायें चलाई हैं जो सीधे तौर पर गरीबों से जुडी हैं और इन योजनाओं का फायदा गरीब लोगों को मिल रहा है। इस योजना के साथ बीमा भी सरकार कर रही है। सत्तर वर्षो में किसी सरकार ने ऐसी सुविधा नहीं दी। सत्तर वर्षो में जिन लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं था उनका सपना मोदी ने साकार किया है। सांसद ने प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना का जिक्र करते हुए कहा की इससे पौने छः करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। बगैर अपनी जमीन और घर गिरबी रखे लोगों को रोजगार लगाने के लिए मोदी सरकार ऋण उपलब्ध करवा रही है। गरीब आदमी अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। ओबीसी के लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को सविधानिक दर्जा मोदी सरकार ने दिलाया।

सांसद ने कहा की आज भी देश की 70 फीसदी महिलायें एनीमिक हैं, क्यूंकि महिलायें अपना कम और परिवार का बच्चों का ज्यादा ध्यान रखती हैं। चूल्हा जलाती हैं जिससे एक बार में तीन सौ सिगरेट का धुँआ उनके फेंफडों में जाता है और वह अस्वस्थ रहती हैं। उज्ज्वला योजना काफी हद तक महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हागी।

सांसद ने बताया की जिला हमीरपुर की 97.34 फीसदी परिवारों के पास गैस कनेक्शन हैं। भाजपा की पूर्व प्रदेश सरकार के समय माता श्रबरी महिला सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदेश में बांटे गये थे। बाकी के तीन प्रतिशत से कम लोगों को भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दे दिए जायेंगे। माता श्रबरी महिला सशक्तिकरण योजना को ही केंद्र सरकार ने आगे बढाया है। ऐसी ही कई और भाजपा की पूर्व प्रदेश सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने किया शिमला-दिल्ली के लिये दो वॉल्वो बसों को रवाना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में अपनी तरह की दो नई यूरो-4 कंपलायन्ट वोल्वो बसों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ये बसें शिमला-दिल्ली रूट पर चलाई जाएंगी। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिये बसों में मोबाईल/लैपटॉप चार्ज करने के लिए प्रत्येक सीट के साथ अलग-अलग यूएसबी पोर्ट्स् की सुविधा दी गई है। इसके अलावा, यात्रियों को मुफ्त वाईफाई इन्टरनेट सेवा भी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिय बस में दोनों ओर रचनात्मक डिजाईन युक्त हिमाचल की छवियों की सराहना की।

यात्रियों को बहु-संग्रहों में से पंसदीदा फिल्म/गाने चुनने की सुविधा होगी, जिसका प्रयोग बस के वाई-फाई

नेटवर्क के माध्यम से किसी भी हैंडहेल्ड डिवाइस से किया जा सकता है। बस में सीमित संख्या में मोबाईल टैबलेटस, इयरफोन तथा मोबाइल चार्जर्स भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें यात्रियों को 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इन सेवाओं के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई वॉल्वो बसें यात्रियों को और अधिक आरामदायी परिवहन सुविधा प्रदान करेंगी।

हि.प्र. पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि प्रयोगिक आधार पर नई मनोरंजन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, और यदि प्रयास सफल रहता है, ये सुविधाएं निगम की अन्य बसों में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

पांच गांवों को आदर्श इको गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय

शिमला/शैल। मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में सिंचाई एवं जन स्वाथ्य विभाग में जल-रक्षकों से सम्बन्धित नीति के लिए हामी भरी। आईटीआई डिप्लोमा धारक योग्य जल-रक्षकों को पम्प ऑपरेटरों तथा फीटरों के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नित नियमों में कोटा दिया जाएगा। 10वीं तथा 12 साल के अनुभव वाले जल-रक्षकों को चौकीदार तथा पम्प एटेडैंटस के पदों के लिए शामिल किया जाएगा। लगभग 1000 बेलदार के वर्तमान पदों को चौकीदार तथा पम्प अटेडेंट के रूप में पुन: नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल-रक्षकों को 2500 रू0 प्रति माह का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा।

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिहं ने की।

बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाकर 1000 रू0 प्रतिमाह करने का निर्णय भी लिया गया।

सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रीमण्डल ने प्रदेश के दूर्गामी तथा जनजातिय क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जनरल डियूटी अधिकारियों को प्रायोजित करने के लिए एक नीति स्वीकृत की है। इन जनरल डियूटी अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न आर्थिक तथा गैर-आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें प्रदेश या प्रदेश के बाहर स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा, डीएम /एमसीएच. डीएनबी करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मंत्रीमण्डल ने कन्याओं को उनके घरद्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए 'बेटी है अनमोल योजना' के अन्तर्गत स्नात्तक स्तर तथा समान्तर कोर्स जिसमें बीई, बीटैक, एमबीबीएस, बीएड तथा एलएलबी शामिल है कर रही बीपीएल परिवारों की कन्याओं को 5000 रू. सालाना की छात्रवृति आरम्भ करने को स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल ने नियमित जेबीटी अध्यापकों की तर्ज पर पैट अध्यापकों को भी वार्षिक वृद्धि प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में पैट अध्यापकों के लिए स्थानान्तरण नीति तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है। पैट अध्यापक रिक्त पद के लिए एक मुश्त स्थानान्तरण अथवा एक स्थान पर तीन साल का कार्यकाल पूरे करने के उपरान्त पद के विरूद्ध या आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण के लिए योग्य होंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विवाह की स्थिति में अन्तर-जिला स्थानान्तरण के लिए केवल महिला पैट शिक्षक ही योग्य होंगी।

बैठक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अनुबन्ध आधार पर वॉक-इन-इन्टरव्यु के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) के 50 पदों को स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के तहसील कार्यालयों में चालकों के 19 पदों को सृजन तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बिवरजिस लिमिटेड में तृतीय श्रेणी के 39 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 33 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में वन विभाग में निजी राहत देते हुए रजिस्ट्रार के तीन पद भरने, अधिक्षक ग्रेड-2 के दो पदों को पदोन्नत कर अधिक्षक ग्रेड-1 में पदोन्नत करने तथा वरिष्ठ सहायकों के 14 पदों को अधिक्षक ग्रेड-2 में तबदील करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रीमण्डल ने सैकेण्डमेंट/प्रतिनियुक्ति आधार पर जिला शिमला के महात्मा गांधी राजकीय इंजिनीयरिंग कॉलेज कोटला (जियोरी) तथा जिला बिलासपुर के हाईड्रो इंजिनीयरिंग कॉलेज बन्दला में निदेशक एवं प्रधानाचार्य के दो पद भरने का निर्णय भी लिया गया है।

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 32 पदों की बहाली तथा परिवर्तन कर जेई (मकैनिकल) तथा जेई (ईलैक्ट्रीकल) के कैडर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में एचपीएसएससी की वर्तमान वेटिंग लिस्ट से कनिष्ठ अभियन्ताओं के 30 पद और कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी) के 40 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में ऊना जिला के बसदेड़ा, लाहौल स्पिति जिला के काजा, शिमला जिला के ज्यूरी और सिरमौर के ददाहू, रोनहाट तथा पझौता (फटी पटेल) में हाल ही में खोले गए महाविद्यालयों के लिए विभिन्न पदों के सृजन व इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पद, युवा सेवा एवं खेल विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति दी।

जिला विधि सेवा प्राधिकरण में सचिवों के चार पद, जबकि प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधीक्षक ग्रेड-2 के तीन पद सृजित करने के अलावा शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर दो कम्प्यूटर ऑपरेटरों और एक डाटा ऐंटरी ऑपरेटर को रखने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के कुनिहार, मण्डी जिला के रिवालसर और हमीरपुर जिला के लम्बलु में उप-तहसील के सृजंन का निर्णय लिया।

कांगड़ा जिला के खुंडियां में नया वन वृत कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

तिब्बती बाल गांवों के निवासियों को उपदान दरों पर राशन उपलब्ध करवाने संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमण्डल ने धर्मशाला स्थित ऐसे 2000 निवासियों को विशेष अनुदान योजना के अन्तर्गत उपदान दरों पर राशन उपलब्ध करवाने को हरी झण्डी दी।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कांगड़ा जिला के नगरोटा-बगवां के अन्तर्गत बलधार में अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में बिलासपुर जिला के भराड़ी और शिमला जिला के जलोग में आईपीएच विभाग के नए उप-मण्डल तथा सोलन में आईपीएच का नया वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के तिसा (भंजराडू) में लोक निर्माण विभाग का नया मण्डल और नकरोड़ में हिमगिरी व लसूई के साथ उपमण्डल खोलने का निर्णय लिया।

निर्णय लिया गया है कि बिलासपुर से नालागढ़ मण्डल और नाहन वृत्त से सोलन मण्डल को अलग कर सोलन में नए प्रादेशिक वन वृत्त की स्थापना की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने जलागम विकास दलों के 116 सदस्यों की सेवाओं को ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज और जिला परिषद के कैडर में समायोजित करने का फैसला किया।

मण्डी जिला की करसोग तहसील के अन्तर्गत सरतयोला व परलोग में पटवारी के दो पदों के साथ दो नए पटवार सर्कल सृजित करने का निर्णय लिया गया।

लोगों को राजस्व संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अन्तर्गत सालग सादी, कांडो नाडी, मालगी-दड़यात, छछेती, सारा-कायला -गातु-नवी और खाली अच्छों मोहालों को भड़ोग-बनेड़ी तहसील ददाहु से पटवार वृत्त अजोली में स्थानांतरित/ पुनर्गठित करने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में घुमारवीं, बैजनाथ-पपरोला,अम्ब-गगरेट, मनिकर्ण व सुन्दरनगर योजना क्षेत्रों, बीड़बिलिंग विशेष योजना क्षेत्र और रोहडू योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप विभिन्न स्कूलों को स्तरोन्नत करने और इनके लिए स्टाफ का सृजन करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने और उन्हें नई पैंशन प्रणाली के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से हिस्सा प्रदान किया जाएगा।

बैठक में शिमला जिला के कुमारसेन के अन्तर्गत अस्थाई पुलिस चौकी सैंज को आवश्यक स्टाफ की सुविधा प्रदान करने सहित स्थायी बनाने को मंजूरी दी।

मण्डी जिला के धर्मपुर पुलिस थाना के अन्तर्गत टिहरा में और बल्ह पुलिस थाना के अन्तर्गत गागल में भी पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें आवश्यक पद भी भरे जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर, बिलासपुर जिला के बिझड़ी-ढटवाल और मण्डी जिला के पद्धर में फायरपोस्ट खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय वाहन चालकों तथा वर्कशाप एसोसिएशन के धुलाई भत्ते को 30 रूपये से बढ़ाकर 60 रूपये करने तथा एक अतिरिक्त वर्दी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल द्वारा किन्नौर जिला के गुरू संज्ञास (गुरू-छन-ग्याड़) मेला रारंग को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने पांच गांवों को आदर्श इको गांव के रूप में विकसित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्णय लिया । इनमें शिमला जिला का चराउ गांव, सिरमौर जिला का देयांथल गांव, किन्नौर का डमरू, चम्बा का भंजराडू तथा बिलासपुर जिला का टेपरा गांव शामिल है।

मंत्रिमण्डल ने आठ पशु अस्पतालों को उप-मण्डलीय पशु अस्पताल में स्तरोन्त करने का निर्णय लिया जिनमें मण्डी ग्रामीण, सिरमौर जिला का संगड़ाह व शिलाई, ऊना जिला का बंगाणा, चम्बा जिला का सलूणी, हमीरपुर जिला का सुजानपुर, कांगड़ा जिला का ज्वालामुखी तथा मण्डी जिला का धर्मपुर अस्पताल

मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नर्सिंग सैल (टीचिंग कैडर) स्थापित करने के लिए दो पद उप-निदेशक(नर्सिंग) तथा प्रधानाचार्य नर्सिंग अधिकारी के सृजित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के अर्की तहसील के गांव देवरा, सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत भुजोण्ड के गतलोग गांव तथा ग्राम पंचायत शामरा के देबड़घाट, कांगडा जिला की ग्राम पंचायत बल्ला के रसेहड़ गांव में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को अपनी मंजूरी प्रदान की ।

मंत्रिमण्डल द्वारा इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला के कार्डियोलॉजी तथा आर्थोपैडिक्टस विभाग में एक पद प्रोफेसर तथा एक पद सहायक प्रोफैसर के सृजित करने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने राजकीय मैडिकल कालेज नाहन में पैथोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफैसर का एक पद भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के धर्मपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धर्मपुर को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी प्रदान की तथा साथ ही 6 पद भरने की भी स्वीकृति प्रदान की ।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के दारपा-बरकाटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा मण्डी जिला के ही धर्मपुर खण्ड के टीहरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शिमला जिला के ग्राम पंचायत बढाल के बढाल गांव में दो पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के मसेरन में आवश्यक स्टाफ सहित तथा सोलन जिला के नौणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला के चबूतरा स्थित स्वास्थ्य उप-केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा शिमला जिला की ग्राम पंचायत मातल के स्वास्थ्य उप-केन्द्र मातल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में निजी क्षेत्र में फिजियोथेरेपी में स्नातक का कोर्स आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया।

हिमाचल में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम पर बल

शिमला/शैल। बिजली बुनियादी ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, और राष्ट्रों के विकास के लिये ऊर्जा अति आवश्यक है। कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, पन बिजली तथा परमाणु ऊर्जा जैसे पारंपरिक संसाधनों से लेकर पवन, सौर, कृषि व घरेलु कचरे जैसे ऊर्जा उत्पादन के व्यवहार्य गैर-परंपरागत संसाधन मौजूद हैं। देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और आने वाले वर्षो में यह मांग और अधिक बढ़ेगी। देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये मौजूदा उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के जरिए स्वच्छ ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिये, सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, पूंजी और ब्याज सब्सिडी, व्यवहार्यता अंतरण वित्त, रियायती ऋण, वित्तीय सहायता जैसे अनेक प्रोत्साहन प्रदान कर अक्षय ऊर्जा संसाधनों को अपनाने के लिये एक सक्रिय भूमिका निभा रही है।

भविष्य में ऊर्जा की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार ऊर्जा विकास एजेंसी '(हिमऊर्जा) के माध्यम से राज्य में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और व्यक्तियों, समुदायों, संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये सौर फोटोवोल्टेइक प्रणाली के प्रभावी और अभिनव उपयोग को प्रदर्शित करना है।

सौर स्ट्रीट लाईट प्रणाली, सौर घरेलू प्रकाश प्रणाली तथा सौर फोटोवोल्टेइक प्रणाली संयंत्रों जैसी सौर फोटोवोल्टेइक प्रणालियों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है। सब्सिडी के अनुमोदन के लिये पंचायतों, संस्थानों और सरकारी विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को केन्द्र को भेजा जाता है। सौर फोटोवोल्टिक पावर संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने के अलावा, आवासीय और सामाजिक क्षेत्र को 70 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

अभी तक, सरकार ने सिरमौर जिला के बड़ू साहिब में 200 किलोवाट सौर ऊर्जा प्लांट, हि.प्र. सचिवालय के लिए 6. 5 किलोवाट, जिला उपायुक्त कार्यालयों में 4 किलोवाट क्षमता के 12 एसपीवी ऊर्जा प्लांट स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार, 10 किलोवाट सौर ऊर्जा प्लांट रनसेर टापू, किब्बर के लिए 10 किलोवाट, राज्य के 216 पुलिस स्टेशनों प्रत्येक के लिए 2 किलोवाट, कांगड़ा जिला में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के लिए 450 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट, रिज मैदान, पुराना बस अड्डा तथा पंचायत भवन शिमला के लिए 55 किलोवाट क्षमता के प्लांट तथा राजभवन शिमला में 25 किलोग्राम सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।

राज्य में व्यक्तिगत तौर पर एक किलोवाट क्षमता के 250 एसपीवी ऊर्जा प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 152 प्लांट स्थापित किए जा चुके है तथा शेष को शीघ्र स्थापित किया जाएगा। हि.प्र. उच्च न्यायालय के लिए 100 किलोवाट एसपीवी ऊर्जा प्लांट, हिप्पा के लिए भी 100 किलोवाट का तथा हि.प्र. विश्वविद्यालय शिमला में 50 किलोवाट एसपीवी ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।

हिमऊर्जा ने रिकांगपिओ के बचत भवन में 5 किलोवाट का प्लांट, अतिरिक्त उपायुक्त काजा तथा बीएसएनएल टावर माने गोम्पा गांव, आईटीवीपी की 43वीं बटालियन, सुगर पवांइट स्पिति वैली, आईटीवीपी सुमदो तथा आईटीआई सोलन प्रत्येक में पांच केवी क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। स्पिति घाटी के मोरमी दोगरी स्थित आईटीवीपी में 10 किलोवाट का प्लांट, जबकि स्पिति घाटी के आईटीवीपी कौरिक, आईटीवीपी बरियोग तथा आईटीवीपी लेपचा प्रत्येक में 2-2 किलोवाट के प्लांट स्थापित किए गए है। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग काजा में 3 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है।

इसके अलावा, 100 किलोवाट क्षमता के 3 एसपीवी ऊर्जा प्लांट शिमला के घण्डल स्थित न्यायिक एकादमी में, एक किलोवाट क्षमता के 14 एसपीवी प्लांट आईपीएच काजा, पांगी तथा भरमौर में व्यक्तिगत तौर 100 परिसरों में प्रत्येक में एक किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए गए है। इसी प्रकार, भारतीय मॅस्कुलर डैस्ट्रॉफी एसोसिएशन सोलन में 50 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट, हिमाचल प्रदेश के 34 न्यायालय परिसरों में 567 किलोवाट के सौर ऊर्जा प्लांट तथा कांगड़ा जिला के बड़ा बंगाल के गांव में 10 किलोवाट क्षमता के 5 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

राज्य सरकार 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की आबादी वाले अनुसूचित जाति गांवों में एसपीवी स्ट्रीट लाईट प्रणालियां स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति घटक योजना के अन्तर्गत धनराशि प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम के आरम्भ होने से अभी तक 7961 एसपीवी लाईटें स्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा, राज्य में गत साढ़े चार वर्षो के दौरान 55, 230 एसपीवी सीएफएल लालटेन, 22,586 एसपीवी घरेलू लाईटें तथा 674 एसपीवी एलईडी घरेलू लाइटें स्थापित की गई हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

प्रदेश में सरकार नही माफिया राज चल रहा है – भाजपा ने लगाया आरोप

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिये ''हिसाब मांगे हिमाचल'' के नाम से चार पन्नों का एक पोस्टरनुमा पर्चा छापकर अपनी नीयत और नीति सार्वजनिक कर दी है। चुनावी संद्धर्भ में आयोजित पहली पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. संबित पात्रा ने यह चर्चा मीडिया को जारी करते हुए न केवल प्रदेश सरकार और इसके मुखिया वीरभद्र सिंह पर हमला बोला बल्कि कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए सावल किया कि वीरभद्र जैसे आरोपों में घिरे नेता को देव भूमि हिमाचल का नेतृत्व क्यों सौंपा? भाजपा के इस चार पन्नो के पोस्टर में सबसे पहले उद्योग मन्त्री मुकेश अग्निहोत्री के उद्योग विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि पिछले चार वर्षो में अवैध खनन के 30,000 से अधिक मामले सामने आये हैं और इनमें प्रदेश को 2400 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। सोलन की एक कंपनी से खनन के लिये मिलने वाली 22.72 करोड़ की रायल्टी और 4. 39 करोड़ का ब्याज क्यों नही वसूला गया यह और सवाल उठाया गया है।

खनन के बाद ड्रग्स को लेकर आरोप लगाया गया है कि इसमें 900 करोड़ का अवैध करोबार चल रहा है और 40% हिमाचली युवा इसके शिकार हो चुके हैं। इससे होने वाली मौते दस गुना बढ़ गयी है। जबकि इस अवैध धन्धे में लिप्त लोगों की गिरफ्तारियों में 30% अधिक की गिरावट आयी है। वन माफिया के नाम पर आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के वन क्षेत्र मे से 54000 हैक्टेयर पर अतिक्रमण हो चुका है। बिल्डर माफिया हर कहीं अन्धाधुन्द अवैध निर्माण में लगा हुआ है और विभाग की मिली भगत से यह निर्माण नियमित भी होते जा रहे हैं। राज्य आपदा राहत कोष से 19 करोड़ रूपया निकालकर सरकारी इमारतों की मुरम्मत पर खर्च कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग ने 9 करोड़ रूपया सड़कों की रिपेयर करने की बजाये अधिकारियों के लिये गाड़ियां खरीदने पर खर्च कर दिया गया। जिन क्षेत्रों में बर्फ पड़ती ही नही वहां पर 20 करोड़ रूपया बर्फ हटाने के नाम पर खर्च कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग की भ्रष्ट कार्य प्रणाली के कारण पांच वर्षो में 500 करोड़ के कोलतार का ही नुकसान कर दिया गया। मंडी में 20 करोड़ की लागत वाली 20 सड़कों को डीपीआर के अनुसार नही बनाया गया और अधूरी सड़को को ही यातायात के लिये खोल दिया गया। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले सस्पेंडिडस्काईवे ट्रांसफोर्ट सिस्टम का ठेका बेला रूस की कंपनी स्काईवे टेक्नोलॉजी को बिना किसी प्रक्रिया के दे दिया गया। पेयजल और सिंचाई योजनाओं में 1053 करोड़ का घोटाला किये जाने का भी आरोप लगाया गया है। जंगी थोपन पवारी जल विद्युत परियोजना में ब्रेकल पावर कारपोरेशन

पर भाजपा सरकार के दौरान 1800 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था लेकिन कांग्रेस सरकार ने न केवल इसे माफ कर दिया बल्कि ब्रेकल से वसूले गये 280 करोड़ के अग्रिम शुल्क को भी वापिस करने का फैसला कर दिया। सोरंग परियोजना का ठेका 20 करोड़ का अग्रिम लिये बिना ही एक अन्तर्राष्ट्रीय कंपनी को दे दिया।

इन आरोपों के अतिरिक्त बागवानी निदेशालय के निदेशक डा. बवेजा मुख्यमन्त्री के प्रधान निजि सचिव सुभाष आहलूवालिया उनकी पत्नी मीरा वालिया रि मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा और मुख्य सचिव वीसी फारखा की नियुक्तियों पर भी गंभीर सवाल उठाये गये हैं। इन आरोपों के अतिरिक्त मुख्यमन्त्री पर व्यक्तिगत रूप से हमला बोलते हुए वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य द्वारा दिल्ली के मैहरौली में खरीदे गये फार्म हाऊस निजि आवास हॉलीलॉज को एक कन्स्ट्रक्शन कंपनी को किराये पर देने आदि के आरोपों को फिर से दोहराया गया है।

भाजपा ने इसी पत्रकार वार्ता में यह भी घोषणा की है कि इस तर्ज पर आने वाले दिनो में चार पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जायेगी। इन वार्ताओं में किसी न किसी मुद्दे पर सरकार से हिसाब मांगा जायेगा। जिस तर्ज पर भाजपा की पहली पत्रकार वार्ता में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर उठाया गया है। उसमें प्रदेश में सरकार नही बल्कि माफिया राज चलने का आरोप लगाया है। आने वाली पत्रकार वार्ताओं में भी सरकार की यही माफिया छवि जनता में उभारने का प्रयास किया जायेगा यह स्पष्ट हो गया है।

भाजपा के आरोपों पर वीरभद्र सरकार या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ठोस प्रतिकार नही आया है। बल्कि सूत्रों के अनुसार जिन विभागों के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं उनसे भी इन आरोपों के बारे में कोई जानकारी नही मांगी गयी है। इससे यही संकेत उभरता है कि या तो सरकार के पास इसका कोई जवाब ही नही है या वह फिर इन्हे गंभीरता से नही ले रही है। लेकिन यह माना जा रहा है कि यदि समय रहते सरकार और संगठन की ओर से कोई काऊंटर नही आता है तो जनता के पास इन्हे सही मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही रह जायेगा।

भाजपा की आक्रामकता केवल राजनीतिक हथकण्डा

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा ने इस बार भी 2012 की तर्ज पर मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह को घेरने की रणनीति अपनाई है। यह संबित पात्रा की पत्रकार वार्ता से स्पष्ट हो गया है। लेकिन 2012 में जिस मुद्दे पर अरूण जेटली ने वीरभद्र पर निशाना साधा था संयोगवश वही मुद्दा आज भी लगभग वैसा ही खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि आयकर के सारे मामले अदालतों में लंबित चल रहे हैं। सीबीआई अपनी जांच पूरी करके चालान अदालत में दायर कर चुकी है। लेकिन उसमें अभी ट्रायल की स्टेज नही आयी है। ईडी दो अटैचमैन्ट आदेश जारी कर चुकी है आधी जांच करके आनन्द चौहान के खिलाफ चालान दायर कर चुकी है और वह एक वर्ष से अधिक समय से ईडी की हिरासत में भी चल रहा है लेकिन ईडी की जांच अभी पूरी नही हुई है और इसी कारण से अनुपूरक चालान दायर नही हो सका है।

सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिये वीरभद्र ने जो याचिका दायर की थी उसका फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस विपिन सांघी की पीठ 31 मार्च 2017 को सुना चुकी है। इस फैसले में वीरभद्र याचिका को अस्वीकार करने के साथ ही अदालत ने मुख्यमन्त्री के 2012 के चुनावों मे दायर शपथ पत्र पर भी चुनाव आयोग को गंभीर निर्देश दे चुकी है। यदि इन निर्देशों पर कारवाई हो जाती तो आज राजनीतिक परिदृश्य एकदम बदला हुआ होता। लेकिन वीरभद्र को भ्रष्टाचार पर घेरने वाली भाजपा ने एक दिन भी इस फैसले पर अपना मुंह नही खोला। संबित पात्रा से जब शैल ने पत्रकार वार्ता में इस संद्धर्भ में सवाल पूछा तो उनके पास इसका कोई जवाब नही था। यही नही जब ईडी के आनन्द चौहान और वीरभद्र को लेकर सामने आये अलग – अलग आचरण पर सवाल पूछा तो इसका भी कोई सन्तोषजनक उत्तर डा. पात्रा के पास नही था।

डा. पात्रा ने वीरभद्र की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि शासन को रिटायर्ड और टायरड अधिकारी चला रहे हैं। लेकिन जब इसी संद्धर्भ में उनसे पूछा कि मोदी मन्त्रीमण्डल में तो दो ऐसे रिटायर्ड नौकरशाहों को मंत्री बना दिया गया है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य ही नही है तो इस सवाल पर भी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पास कोई उत्तर नही था। इस संद्धर्भ में यदि भाजपा की इस चुनावी आक्रामकता का आंकलन किया जाये तो स्पष्ट उभरता है कि सही मायनों में भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई गंभीर नही है। यदि गंभीर होती तो जनता से वायदा करती कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों पर वह आज ही विजिलैन्स में विधिवत शिकायत दर्ज करवा कर एफआईआर दर्ज किये जाने की मांग करती और यदि विजिलैन्स मामला दर्ज न करती तो वह सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाकर इन आरोपों को अंजाम तक पहुंचाती। लेकिन भाजपा की ओर से ऐसा कोई वायदा और कारवाई सामने न आने से स्पष्ट हो जाता है कि उसे यह आरोप केवल चुनाव प्रचार के लिये चाहिये।

भाजपा की शिकायत पर अभी तक दर्ज नही हुई एफआईआर

शिमला/शैल। भाजपा के संभावित चुनाव प्रत्याशीयो की सूची सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पार्टी के अन्दर मचे घमासान को शांत करने के लिये प्रदेश पुलिस के साईबर सैल में पार्टी ने एक शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि किन्ही शरारती तत्वों ने उम्मीदवारो की फर्जी सूची तैयार करके सोशल मीडिया में जारी कर दी है। यह सूची जारी होने के बाद इस पर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से लेकर पंचकुला में हुई कोर कमेटी की बैठक तक मे इस वायरल सूची पर चर्चा हुई है। यह सूची सामने आने के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के समीकरणों में कई फेरबदल चर्चा में है। इसी सूची का प्रभाव है कि शिमला के कुसुमप्टी विधानसभा क्षेत्र से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से ताल्लुक रखने का दावा करने वाले एक एनडी शर्मा ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। रामपुर, सोलन, बिलासपुर में समीकरण बदलने की चर्चाएं सामने आ रही है। इस पार्टी द्वारा साईबर सैल का भेजी शिकायत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

लेकिन इस शिकायत पर अब तक साईबर सैल में कोई एफआईआर दर्ज नही की गयी है और न ही भाजपा यह एफआईआर दर्ज करने की मांग ही कर रही है। क्योंकि जो सूची वायरल हुई है उसमें दिल्ली में केन्द्रिय चुनाव कमेटी की बैठक में इन नामों की चर्चा होने का जिक्र दर्ज है बैठक के बाद स्वास्थ्य मन्त्री नड्डा के ईमेल से यह सूची प्रदेश अध्यक्ष सत्ती को उनकी मेल पर भेजी गयी। ऐसे में साईबर जांच की थोड़ी सी समझ रखने वाला भी यह जानता है कि इसकी जांच की शुरूआत नड्डा और सत्ती की ईमेल खंगालने से शुरू होगी। इसी के साथ केन्द्रिय चुनाव कमेटी की बैठक की जानकारी लेनी होगी इस जानकरी के साथ ही इन नेताओं की फोन काल्ज़ तक रिकार्ड कब्जे में लेना आवश्यक होगा। परन्तु अभी तक जांच में ऐसा कोई कदम उठाये जाने की कोई सूचना नही आयी है। सूत्रों की माने तो भाजपा के शीर्ष नेता भी ऐसी जांच के पक्षधर नही है। और इस शिकायत को जल्दीबाजी में उठाया गया कदम मान रहे है।

अब रवि शंकर प्रसाद ने

.....पृष्ठ 1 का शेष

ये लिंग का मामला हैं। ये नारी समानता, नारी अस्मिता और नारी गरिमा का मामला हैं।

उन्होंने प्रदेश की जनता से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का आहवान किया। कांग्रेस नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने के मसले पर उन्होंने कहा पार्टी गुण दोष के आधार पर फैसला लेगी।

याद रहे कि वीरभद्र सिंह सरकार के क्रप्शन पर 2012 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के राष्ट्रीय नेता अरुण जेटली ने इल्जाम लगाए थे। उनका क्रप्शन तब के चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई थी।

इसके बाद धूमल व उनके परिवार ने इन्हीं आरोपों को लेकर पिछले साढे तीन सालों तक जमकर शोर हल्ला मचाया। वो पिछले एक डेढ साल से मौन हैं। कहा ये जाता है कि कोई डील हो गई है। वीरभद्र सिंह चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र है तो सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। तब ईडी ने अपना पंजा उनकी ओर बढ़ाया और वीरभद्र के मुंशी आनंद चौहान को अरेस्ट कर लिया। वो सवा साल से जेल में हैं। बताते है कि इस बीच फिर कोई डील हुई और वीरभद्र सिंह को ईडी ने आज तक अरेस्ट ही नहीं किया। न ही बाकी आरोपियों को पकड़ा।

अब भाजपा चुनावों के दौरान उनके क्रप्शन को मुख्य मुद्दा बना रही हैं। लेकिन अंदरखाते से सौदों की अफवाहें भी है।